



पेज 7 | जयपुर

सच के साथ सुप्रभात

मॉर्निंग न्यूज़

वर्ष 22 अंक : 151 ₹ 4.00 पृष्ठ-8

www.morningnewsindia.com

जयपुर, शुक्रवार 9 अक्टूबर, 2026

आज फिर चलेगा बुलडोजर, व्यापारियों ने जलाए टायर

3

ख़ुशख़बरी : त्योहारी सीजन में टल सकता है यूपीआई चार्ज

15 अक्टूबर से लागू होना था 0.4% चार्ज का नियम, अब 1 जनवरी से करने की तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)

यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को लेकर चिंतित व्यापारियों के लिए एक खुशखबरी है। केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय में इस बात को लेकर विचार हो रहा है कि दीपावली के सीजन के दौरान इसको टाला जाए। केन्द्र सरकार 15 अक्टूबर से 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाने का नियम लागू करने वाली थी।

सूत्रों का दावा है कि सरकार अगले साल 1 जनवरी से नया नियम लागू करने पर विचार कर रही है। ऐसा हुआ तो फेस्टिव सीजन में दुकानदारों और पेमेंट कंपनियों को छूट दी जा सकती है यानी

यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा। सूत्रों का कहना है कि फेस्टिव सीजन के दौरान दुकानदारों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े इसलिए सरकार 0.4% मर्चेट शुल्क लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने का मन बना रही है। सरकार की ओर से आधिकारिक फैसला अगले कुछ ही दिनों में सामने आ सकता है।

इस बीच गिरे यूपीआई कम्पनियों के शेयर : यूपीआई पर मर्चेट चार्ज टलने की खबर का सीधा असर शेयर बाजार में लिस्टेड फिनटेक कंपनियों के शेयरों पर देखा। ट्रेडिंग के दौरान पेट्रीएम का शेयर एक वक्त 10% तक टूटकर 1,561 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, बाजार बंद होते-होते इसमें थोड़ा सुधार हुआ और यह 5.42% की गिरावट के



साथ 1,640 पर बंद हुआ। मोबिविक्क के दिन के

कारोबार में शेयर 8.43% गिरकर 235 तक चला गया था, लेकिन मार्केट क्लोज होने पर 4.57% की टूट के साथ 245 पर बंद हुआ। पाइन लैम्ब्स का शेयर 169 के निचले स्तर को छूने के बाद 4.39% की गिरावट लेकर 170 पर बंद हुआ।

क्या करने वाली थी सरकार : यूपीआई से महीने में एक लाख से ज्यादा कमाने वाले व्यापारियों को 2,000 से ज्यादा के हर पेमेंट लेने पर 0.4% एमडीआर प्लस जीएसटी देना होगा। जीएसटी की गणना एमडीआर चार्ज के 18% पर होनी है। जिन व्यापारियों की महीने में यूपीआई से कुल कमाई एक लाख तक है, उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे ट्रांजैक्शन 2,000 से ज्यादा ही क्यों न हो। अगर कोई

छोटा दुकानदार लगातार 3 महीने तक एक लाख से ज्यादा यूपीआई कलेक्शन लेता है, तो बैंक उसे ऑटोमेटिक 'बड़े मर्चेट' की कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। फिर उसे भी चार्ज देना होगा। बड़े व्यापारियों को भी 2,000 या उससे कम के छोटे पेमेंट्स पर कोई फीस नहीं देनी होगी। 75,000 या उससे बड़े ट्रांजैक्शन पर मर्चेट से मैक्सिमम 300 प्लस जीएसटी ही चार्ज लिया जाएगा। 2,000 की लिमिट पूरे दिन की कुल बिक्री पर नहीं, बल्कि हर एक पेमेंट पर देखी जाएगी। पेट्रोल पंप, रेलवे, बिल पेमेंट, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और एजुकेशन से जुड़े व्यापारियों को 2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.40% के बजाय फ्लैट रूपए 5 देना होगा।

फर्स्ट कॉलम

रणभेरी : पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी, 22 को मतदान

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज़)। प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों की रणभेरी बज गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।



आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए लोक सूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रथम चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन पत्र 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी। इसके बाद प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेने का मौका दिया जाएगा। 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की अंतिम समय सीमा तय की गई है। नाम वापसी की अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रथम चरण का मतदान 22 अक्टूबर को होगा।

322 नेता चुनाव लड़ने के योग्य नहीं : प्रदेश में पंचायत राज चुनाव से पूर्व पंचायत राज विभाग ने एक सूची निर्वाचन आयोग को भेजी थी जिसमें 322 नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य बताया है। इस पर आयोग ने इन सभी नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया है। निर्वाचन आयोग के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार जो अयोग्य ठहराए गए हैं वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये सूची भेज दी गई है।

एअर इंडिया की इंटरनेशनल उड़ानें 17 हजार तक महंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। एअर इंडिया की फ्लाइट में आज से सफर करना महंगा हो जाएगा। इंडिगो के बाद एयरलाइन ने भी घरेलू उड़ानों में 1200 रूपए तक और इंटरनेशनल उड़ानों में 17,800 रूपए तक एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लगाने का ऐलान किया है।

नए फ्यूल चार्ज एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी लागू होंगे, क्योंकि दोनों टायट ग्रुप की एयरलाइन हैं। नई कीमतें 9 अक्टूबर रात 12:01 बजे से लागू होंगी। एयरलाइन ने यह फैसला एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल महंगा होने की वजह से लिया है। एअर इंडिया ने 7 महीने में तीसरी बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है।

अब जीएसटी अफसर को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। 5 करोड़ से कम की टैक्स चोरी या गड़बड़ी करने वालों को टैक्स अधिकारी अब किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकेंगे। यह फैसला गुस्वार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में लिया गया। बैठक में जीएसटी मामलों में क्रिमिनल केस की मिनिमम लिमिट 1 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए कर दी गई है। 5 करोड़ रूपए से कम की गड़बड़ी को सिर्फ गुर्माना भरकर सुलझाया जा सकेगा। 10 हजार रूपए से कम की टैक्स चोरी पर कारोबारी को नोटिस भी नहीं दिया जाएगा।

मोबाइल आमजन तक सरकारी मदद पहुंचाने का जरिया बना : प्रधानमंत्री

‘मोबाइल कांग्रेस’ के दूसरे दिन पीएम शामिल हुए कहा-5 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचे

नई दिल्ली (एजेंसी)

इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कहा कि आज सरकार की बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तर जैसी सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल पर हैं। इसी पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अब तक करीब 50 लाख करोड़ रूपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। इस सिस्टम की वजह से बिचौलियों और फर्जीवाड़े पर रोक लगी और लगभग 5 लाख करोड़ रूपए गलत हाथों में जाने से बच गए। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एआई और 6जी पर फोकस रहेगा। 2017 में हुआ पहला इवेंट सिर्फ भारत पर फोकस्ड था, अब 100 से ज्यादा देश शामिल हुए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि आज मोबाइल फोन केवल गपशप या चैट करने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह आम लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। भाषा या दूरी को



रकावटें खत्म हो गई हैं। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बच रहा है।

सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में रफ्तार पकड़ रहा भारत : पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी रफ्तार पकड़ रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज में हमारा फोकस सप्लाय चेन पर है। हम इसमें बड़े कदम उठा रहे हैं। बीते साल में हमने काफी कुछ हासिल

किया है, लेकिन अब नए पड़ाव पार करने हैं। इसके लिए हमें प्रयासों को व्यापक करते रहना है। मोदी ने कहा कि मैं जीएसएमए और दुनिया के ऑपरेटर से कहना चाहूंगा कि ऐसा नेटवर्क बनाए कि गलत लोगों को पहुंचने से रोके। भारत ने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। बीते साल में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। अब डिजाइन भी भारत में होगा, टेक्नोलॉजी भी भारत की होगी। रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है।

साहित्य का नोबेल कनाडाई लेखिका ऐन कार्सन को



स्टॉकहोम (एजेंसी)। कनाडा की लेखिका ऐन कार्सन को 2026 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति ने उन्हें ऐसी रचनाओं के लिए सम्मानित किया है, जिन्हें उन्होंने प्राचीन ग्रीक-रोमन साहित्य और परंपराओं को नए तरीके से पेश किया। उन्होंने कविता, कहानी और नाटक जैसे साहित्यिक रूपों को मिलाकर लिखने के नए तरीके भी अपनाए हैं। ऐन कार्सन का जन्म 1950 में कनाडा के टोरंटो में हुआ था। उन्होंने 1981 में क्लासिक्स विषय में 'ओडी एट अमो एगो सम' नाम से डॉक्टरेट थीसिस प्रकाशित की। इसके बाद उन्होंने कविता लेखन के साथ प्राचीन ग्रीक साहित्य का अनुवाद किया और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया। उनके लेखन में

शब्दों की उत्पत्ति और उनके नए अर्थ तलाशने पर खास जोर रहा है। उन्होंने यूनानी कवयित्री सैफो की कविताओं और नाटककार सोफोक्लीज की 'इलेक्ट्रा' व 'एंटीगोन' जैसी रचनाओं का अनुवाद भी किया। 1986 में प्रकाशित 'इरोस द बिटरस्वीट' को उनके आगे के लेखन की नींव माना जाता है। इसमें उन्होंने प्राचीन ग्रीक साहित्य के जरिए प्रेम और इच्छा को समझाया। उनके मुताबिक, प्रेम में खुशी और दर्द दोनों शामिल हो सकते हैं। कार्सन की खासियत अलग-अलग दौर के लेखकों को एक ही रचना में साथ रखना है। 1999 की 'इकोनॉमी ऑफ द अनलॉस्ट' में उन्होंने प्राचीन यूनानी कवि सिमोनाइड्स को आधुनिक कवि पॉल सेलान के साथ रखा।

योजनाएं

149 ग्राम पंचायतों के 324 गांवों में पीवीटीजी समुदाय को मिल रही मूलभूत सुविधाएं

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में विकास को गति दे रहा ‘पीएम-जनमन’

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज़)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) में बारां जिले के किशनगंज, शाहबाद सहित 8 ब्लॉकों में आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और आंगनबाड़ी जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सहरिया पीवीटीजी जनजाति की आबादी सारांज 1 लाख 30 हजार है, जो बारां जिले

की 149 ग्राम पंचायतों के 324 राजस्व ग्रामों में निवास करते हैं। पीएम-जनमन के अंतर्गत राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 14 हजार 671 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में 4 हजार से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन तथा 16 हजार से अधिक वॉल्वेंट एवं पात्र परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। साथ ही, जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए 22 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। जनजातीय युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। पीएम-जनमन के तहत 15



मल्टीपर्सन सेंटर, 51 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 51 वन-धन केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 2 छात्रावासों का कार्य पूर्ण हो चुका है और 19 अन्य छात्रावासों का कार्य जून 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।

देवास परियोजना के तृतीय और चतुर्थ चरण के कार्यों में अभूतपूर्व तेजी

: वहीं उदयपुर की दीर्घकालीन जल सुरक्षा की दिशा में बेहद अहम देवास परियोजना के तृतीय और चतुर्थ चरण के अन्तर्गत बांध एवं टनल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में इस अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण परियोजना के अन्तर्गत साबरमती बेसिन का जो अमूल्य जल व्यर्थ बहकर अरब सागर में चला जाता था, उसे बनास बेसिन की ओर अपवर्तित कर उदयपुर की जल व्यवस्था से जोड़ने का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। देवास-चतुर्थ परियोजना के अंतर्गत गोरगुदा तहसील के अंबावा गांव के पास 390 एमसीएफटी क्षमता के बांध तथा 4.15 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है। यहां से जल का

अपवर्तन देवास-तृतीय परियोजना की ओर किया जाएगा। इसी प्रकार नाथियाथल गांव के पास 703 एमसीएफटी क्षमता के देवास-तृतीय बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध से जल को 10.50 किलोमीटर लंबी टनल के माध्यम से मौजूदा देवास-द्वितीय (आकोदड़ा बांध) तक आवश्यकतानुसार पिछोला झील तक आवश्यकतानुसार पिछोला झील में अपवर्तित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उदयपुर की जल सुरक्षा के लिए 1974 में देवास का प्रथम चरण शुरू हुआ था। इसके बाद देवास-द्वितीय वर्ष 2015 में पूर्ण हुआ, जिसके अंतर्गत आकोदड़ा बांध एवं सुरंग प्रणाली के माध्यम से गुरुत्व प्रभाव द्वारा जल को उदयपुर की पिछोला झील तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित हुई।